

subsidy for purchase of fertilizers to small farmers whose fertile land has been overrun by recent heavy floods in Saurashtra and Kutch regions of Gujarat;

(b) if so, what action Government have taken to meet the demand, details and timing as well as mechanism thereof; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) In a preliminary report the State Government has indicated that about Rs. 10 crores will be required for meeting the various needs of the agriculturists such as seeds and other agricultural inputs like fertilisers.

(b) and (c) The question of providing subsidy will be considered as and when a formal request for such assistance is received from the State Government who have informed that actual damages are being assessed.

Financial Assistance sought by Himachal Pradesh for conserving forests

23. SHRIMATI USHA MALHOTRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Himachal Pradesh Government have proposed the phased reduction in the felling of trees for conserving forests and sought financial assistance from the Central Government to make up the loss of revenue on that account;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what action the Central Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Himachal Pradesh Government has proposed a policy to reduce the commercial exploitation of Government forests by 25 per cent during the current year and of an equivalent order in the succeeding years so as to achieve complete moratorium on commercial felling of trees on government account by the year 1983-84.

Government of Himachal Pradesh has estimated that this would result in the loss of revenues as under:

	(Rs. in crores)
1981-82	2.5
1982-83	6.0
1983-84	10.0
1984-85	14.0

The total loss of revenue during the remaining period of the current Five Year Plan is thus likely to be of the order of Rs. 32.50 crores. They have requested that this loss in revenue may be made good by giving special assistance to Himachal Pradesh.

(c) The matter is under consideration.

Public Call Offices for Districts of Maharashtra

24. SHRI G. R. MHAISEKAR: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the number of public call offices sanctioned for the districts of Aurangabad, Bhil, Nanded, Osmanabad and Parbhani in Maharashtra;

(b) whether it is a fact that a number of sanctioned public call offices are awaiting execution though the people of these places have paid their contributions; and

(c) what is the number of places wherefrom the contributions have been received?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(SHRI KARTIK ORAON): (a)

S.No.	Dis rict	Long distance Public Telephones sanctioned
1	Aurangabad . . .	21
2	Bhir . . .	25
3	Nanded . . .	6
4	Parbhani . . .	15
5	Osmanabad . . .	16

(b) There is no case of any sanction-
ed long distance P.C.O. where contri-
butions have been received awaiting
execution.

(c) Nil.

12 Noon

RE THE TREATMENT METED OUT
TO SHRI RAMESHWAR SINGH,
MEMBER RAJYA SABHA, BY THE
POLICE AFTER HIS ARREST ON
THE 8TH JULY 1980, IN CONNEC-
TION WITH THE BAGHPAT AGITA-
TION

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) :
श्रीमान्, 8 तारीख को मेरी गिरफ्तारी बाग-
पत में हुई थी। इंग्लैण्ड मैंने एक नोटिस
आपको दिया था। उस नोटिस के संबंध
में आपने अभी तक कुछ नहीं बताया।
मेरी जो गिरफ्तारी बागपत में हुई थी और
मेरे साथ जो व्यवहार पुलिस वालों ने
किया उस पर मैं अपनी बात रखूंगा।

हम 8 तारीख को एक बजे दिन में
गिरफ्तार किये गये और सारा दिन हम
को मेरठ शहर में रूमाया गया। सात बजे
तक हम को बस में ही रखा गया जो कि
खुली हुई थी। वहां जब मेरठ जेल में
जगह नहीं मिली तो हम को वहां से करीब

240 किलोमीटर दूर खुली गाड़ी में बरेली
ले जाने की व्यवस्था की गई। शाम को
सात बजे वहां से बरेली ले जाने का प्रबन्ध
किया गया और हमें करीब ढाई बजे
रात को बरेली पहुंचाया गया। रात भर
हम को बस में उसी तरह से रखा गया।
हम को और हमारे साथियों को भीर में
चार बजे जेल में प्रवेश कराया गया।
इसी बीच हमारे लिये कहीं न तो पानी
की व्यवस्था की गई और न ही चाय
आदि की। यही नहीं अगले दिन भी हमारे
लिये खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई
क्योंकि जेल अधिकारियों को यह पता नहीं
था कि ये लोग आ रहे हैं। जब मेरी गिरफ्-
तारी 8 तारीख को हुई तो वहां पर जो
मजिस्ट्रेट था उनके सामने मैंने कबूल किया
था कि हमने धारा 144 तोड़ी है। पुलिस
ने जो ज्यादाती की है, महिला के साथ
जो रेप किया है और तीन आदिमियों को
मारा है उसके विरोध में हम सत्याग्रह
कर रहे हैं। श्रीमान्, उस गंगी औरत को
चौराहे पर घुमाया गया। जब हमने
यह बात मजिस्ट्रेट को कही तो मजिस्ट्रेट
ने हमको बताया कि हम आपको सजा
नहीं दे सकते। 9 तारीख की डेट दी गई
लेकिन 9 तारीख को हमको बरेली से नहीं
बुलाया गया। फिर मजिस्ट्रेट ने 14
की डेट दी। आप हमारी इस बात पर
यकीन करें कि 14 तारीख को कोर्ट में
पेश होने की व्यवस्था करने के लिये हम
को 13 तारीख को शाम को सात बजे बस से
बरेली बे लाया गया। बारिश हो रही थी।
हमारे लिये कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई।
हमारे लोगों की चार-पांच गाड़ियां ला
कर पुलिस लाइन के सामने खड़ी कर दी।
रात भर हम को बस में रखा गया। रात
भर ही नहीं अगले दिन भी 14 तारीख
को 10 बजे तक हम को बस में रखा
गया। हम लोगों को चाय तो क्या पानी
तक नहीं दिया गया पीने के लिये।
इधर उधर पुलिस के लोग दौड़ रहे थे